

मूकपत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02 अंक – 281 बेमेतरा, रविवार 07 जून 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज – 08 मूल्य – 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

समाचार सार

गूगल ने गुरुग्राम में ली 6.17 लाख वर्ग फुट जगह

नईदिल्ली। टेक दिग्गज गूगल इंडिया ने देश के कर्मशियल रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ी डील की है। कंपनी ने गुरुग्राम के ‘एट्रियम प्लेस’ में करीब 6,17,000 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। प्रॉपर्टी के एक्सेस किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, 5 साल के लिए होने वाली इस डील का कुल किराया करीब 671 करोड़ रुपये है। यह नया ऑफिस स्पेस एट्रियम प्लेस के टॉवर 1 में स्थित है, जो डीएलएफ और हाइन्स का एक जॉइंट वेंचर है। इस एग्रीमेंट के तहत गूगल 617,448 वर्ग फुट जगह के लिए करीब 10.55 करोड़ रुपये का मासिक किराया देगा। लीज की दर 171 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। अप्रैल 2026 में रजिस्टर्ड हुए इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, गूगल ने सिन्क्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 63.65 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

सरकारी साइबर सुरक्षा को मिलेगा एआई का साथ

नईदिल्ली। भारत की कुछ चुनिंदा सरकारी एजेंसियों को एंथ्रोपिक के क्लांड मिथॉस तक सीमित पहुंच मिलने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इनमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), भारतीय कैंस्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन्), नेशनल क्रिटिकल इन्फोमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) और दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटीलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि इन सरकारी विभागों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के महत्त्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे में कमजोरियों की जांच करने के लिए शुरुआत में परीक्षण के तौर पर और बाद में पूरी तरह तैनाती के लिए सीमित पहुंच दी जा सकती है।

यूपी से मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए चलेगी 2 नई स्पेशल ट्रेनें

नईदिल्ली। भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधाजनक रेल यात्रा के लिए दो नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के उधना तक चलाई जाएंगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इन दोनों स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी सारी अहम जानकारीयां साझा की हैं। प्रयागराज के सुबेदारनंज से इंदौर के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन 15 जून से 29 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सेवाएं देगी। इसी तरह, इंदौर से सुबेदारनंज तक चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन 16 जून से 29 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सेवाएं देगी। इस स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी का 1, स्लीपर क्लास के 8, जनरल क्लास के 8 और एक्स्प्रेसआरबी के 2 डिब्बे समेत कुल 19 डिब्बे होंगे।

कार्यक्रम में भारत की सात प्रीमियम आम किस्मों को पेश किया गया, जिनमें अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसे मशहूर आम शामिल थे। खास बात यह रही कि अमेरिकी रिटेल कंपनी कॉस्टको के स्टोर में भारतीय आम पहुंचते ही सिर्फ दो घंटे के भीतर पूरा स्टॉक बिक गया। इससे साफ हो गया कि भारतीय आमों की मांग अब वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। सिएटल स्थित भारतीय

आम की छांव में मुख्यमंत्री की चौपाल, खाट पर बैठे, ग्रामीणों की सुनी बात, मौके पर दिए समाधान

सीएम साय ने की निमधा में नर्सिंग कॉलेज मिनी स्टेडियम और मंगल भवन की घोषणा

लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी, महिलाओं को दिया करोड़पति दीदी बनने का मंत्र

स्व-सहायता समूहों की सफलता को मिली नई पहचान, मुख्यमंत्री ने किया आजीविका गाथा कॉफी टेबल बुक का विमोचन

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का मरवाही विकासखंड के ग्राम निमधा में एक अनूठा और आत्मीय जनसंवाद देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांव के बीच आम के पेड़ की छांव में खाट पर बैठकर ग्रामीणों से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं सुनीं और शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष फीडबैक लिया। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि



राज्य सरकार द्वारा 1 मई से 10 जून तक पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव है, उनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जबकि अन्य मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों और मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम तथा सर्वसमाज के लिए विशाल मंगल भवन की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान

करते हुए तीनों मांगों को तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए उनकी घोषणा की। ग्रामीणों द्वारा बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएं उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से जानकारी ली और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे। जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: नशीली सिरप खपाने ग्राहक ढूंढ रहा आरोपी गिरफ्तार, 1.40 लाख का माल जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर के दिशा-निर्देश में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

इसी कड़ी में नशीली सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक लाख रुपए से ज्यादा का 249 नग कोडीन नशीली सिरप जब्त किया गया है। यह पूरा मामला गुडियारी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, 5 जून



को गुडियारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झाबक पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अपने बैग में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप लेकर खड़ा है और उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश

कर रहा है। सूचना मिलते ही डीसीपी मयंक गुर्जर ने एडिशनल डीसीपी (नॉर्थ) आकाश मरकाम और सीएसपी पूर्णिमा लामा को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गुडियारी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए हुए लिए के आधार पर घेराबंदी कर पेट्रोल पंप के पास से एक युवक को दबोचा।

लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के कार्यक्रम में हंगामा, असहमति के सवाल पर तीखी बहस

लंदन (ए)। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक कार्यक्रम में दर्शकों के व्यवहार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। दरअसल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कबेक कॉलेज में आयोजित एक लेक्चर के दौरान भारत में असहमति को लेकर सवाल उठा रही एक महिला दर्शक को बीच में ही टोक दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

एआई के लेक्चर में उठा असहमति का मुद्दा- यह पूरा विवाद चार जून 2026 को हुआ, जब सीजेआई सूर्यकांत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ विषय पर व्याख्यान



भारतीय दूतावास ने जताई कड़ी आपत्ति

दे रहे थे। भाषण के बाद जब सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो दर्शकों में मौजूद एक महिला ने भारत में लोकतंत्र और असहमति के प्रति बढ़ती कथित शत्रुता को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

महिला ने सीजेआई के पुराने बयानों का हवाला देते हुए जैसे ही अपनी बात आगे बढ़ानी चाही, मंच

संचालक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। संचालक ने कहा कि पूरे सम्मान के साथ, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इस सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आज की चर्चा का विषय केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून तक सीमित है। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद अन्य दर्शकों ने इस पर विरोध भी जताया। भारतीय उच्चायोग ने आचरण को बताया अस्वीकार्य- इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर दर्शकों के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई। भारतीय दूतावास ने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह का अभद्र व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

अल्फांसो से दशहरी तक के दीवाने हुए अमेरिकी

अमेरिका में छाया भारतीय आमों का जादू: दो घंटे में बिका पूरा स्टॉक

न्यूयॉर्क (ए)। भारतीय आम का स्वाद अब अमेरिका में भी लोगों को खूब पसंद आने लगा है। अमेरिका के सिंएटल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित मैगो मैजिक कार्यक्रम में भारतीय आमों की ऐसी धूम मची कि अमेरिकी ग्राहक और बड़े रिटेल कारोबारी भी इसके दीवाने हो गए।



वाणिज्य दूतावास ने मैगो मैजिक-प्रमोशन एंड टैस्टिंग इवेंट ऑफ इंडियन मैंगोज का दूसरा संस्करण आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय फलों के बड़े आयातकों और अमेरिकी रिटेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र का अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा और दशहरी तथा गुजरात का राजापुरी आम पेश किया गया। लोगों ने इन

आमों का स्वाद चखा और भारतीय व्यंजनों में आम से बने खास पकवानों का आनंद लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय आमों को अमेरिकी बाजार में और ज्यादा लोकप्रिय बनाना था। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के उप-राज्यपाल डेनी हेक ने भारतीय आमों की तारीफ करते हुए कहा कि वह अब कभी आमों को उपलब्धता का पहला दिन नहीं छोड़ेंगे। वहीं कॉस्टको के फ्रेश प्रोड्यूस विभाग के उपाध्यक्ष बॉब हस्की ने कहा कि उनकी कंपनी ने हाल ही में भारतीय केसर आम बेचना शुरू किया और मांग इतनी ज्यादा रही कि स्टॉक तुरंत खत्म हो गया।

उन्होंने कहा कि कंपनी भारतीय आम बेचकर बेहद खुश है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय आमों को अमेरिका में शानदार प्रतिक्रिया

मिली हो। इससे पहले भी भारतीय फलों और कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। कॉस्टको ने हाल ही

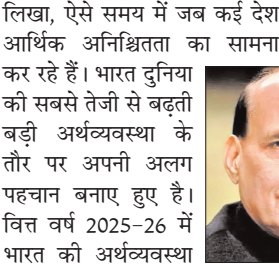
भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है?

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आम पैदा करने वाला देश है। यहां हर साल 2.6 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा आम का उत्पादन होता है और 1000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। अमेरिका में भारतीय आमों का निर्यात 2007 में दोबारा शुरू हुआ था और तब से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को भारतीय आमों का निर्यात 1 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 130 प्रतिशत ज्यादा था। इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

क्या भारतीय आम वैश्विक ब्रांड बनते जा रहे हैं?

भारतीय आमों की बढ़ती मांग यह दिखाती है कि अब भारतीय कृषि उत्पाद वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बना रहे हैं। अल्फांसो और केसर जैसे आम पहले ही दुनियाभर में मशहूर हैं, लेकिन अब दशहरी, लंगड़ा और हिमायत जैसी किस्में भी विदेशी बाजार में पहचान बना रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निर्यात और सप्लाय चेन को और मजबूत किया जाए, तो भारतीय आम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं।

मैं अमेरिका के कई बड़े शहरों में भारतीय केसर आमों की पहली खेप पहुंचाई।



लिखा, ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था

7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी और चौथी तिमाही में यह रफ्तार बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। यह भारत की मजबूती और उस ठोस आधार को

दिखाता है, जिसे पिछले 12 वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के जरिए तैयार किया गया है। इस दौरान, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुलाकात करने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थिरता, आत्मविश्वास, टिकाऊपन और विश्वसनीयता को भी आगे बढ़ाया

ट्रंप ने की मोजतबा से मुलाकात की पेशकश अराघची ने कसा तंज, कहा- असल दुनिया में नहीं जी रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिक (ए)। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई से मुलाकात करने की इच्छा जताई है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तंज कसा है। अराघची ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें वास्तविक दुनिया में रहने की सलाह दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि अगर तेहरान के साथ कोई ठोस समझौता होता है, तो वह ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा कि इस मुलाकात से वह सम्मानित महसूस करेंगे। जब लेबनानी मीडिया ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से ट्रंप की इस टिप्पणी पर सवाल पूछा, तो उन्होंने व्यावहारिक होने की बात कही। अराघची ने कहा कि मैंने वह रिपोर्ट देखी है जिसमें ट्रंप ने मुलाकात का आदान-प्रदान जारी है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें व्यावहारिक होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति को हवा में बातें करने के बजाय असली दुनिया में सोचना और जीना चाहिए।

युद्ध के बीच नए सर्वोच्च नेता की सुरक्षा

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इस्राइली हमलों में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद मार्च में उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री अराघची ने साफ किया कि देश के मामलों पर नए सर्वोच्च नेता का पूरा नियंत्रण है। सुरक्षा कारणों और युद्ध की संवेदनशीलता की वजह से वे अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच इस साल आठ अप्रैल से नाजुक संघर्षविराम लागू है। हालांकि, दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए प्रदेशों का आदान-प्रदान जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी स्थायी समझौते या कूटनीतिक बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं देखी गई है।

स्ट्रट ऑफ होर्मुज में गतिरोध- इस पूरे युद्ध और कूटनीतिक रस्साकशी का सीधा असर



कर्मचारियों से भी बातचीत की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बात की और स्वच्छता बनाए रखने के उनके प्रयासों की सराहना की। कर्मचारियों ने इस बात पर खुशी जताई कि उनकी चिंताएं और सुझाव सीधे रेल मंत्री तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों में शहर के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में निर्माण और संचालन में शामिल लोगों की भूमिकाओं की भी सराहना की।

मंत्री ने नेटवर्क को और आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चल रही मेट्रो विस्तार परियोजनाओं से कोलकाता भर में कमिक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में काफी सुधार होगा। अपनी ऑटो-रिक्षा यात्रा के दौरान, वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में सप्ता में आई भारतीय

जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के डर को दूर भागाओ, भरोसा रखो अभियान पर प्रकाश डाला। रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्य सरकार मेट्रो लिंक को उत्तर में बैरकपुर तक विस्तारित करने के लिए उत्सुक है। हालांकि सर्वेक्षण और रेखाचित्र पूरे हो चुके थे, लेकिन पूर्व सरकार ने बीटी रोड के नीचे पानी की पाइपलाइन की मौजूदगी का हवाला देते हुए इसमें बाधा से हुई है।। यह परियोजना उत्तरी उपनगरों से प्रतिदिन कोलकाता आने-जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी। मेट्रो रेलवे राजारहाट होते हुए गरिया-हवाई अड्डे के निर्माणाधीन मार्ग को पूरा करने के लिए भी उत्सुक है।

रक्षा मंत्री सिंह ने भारत की जीडीपी वृद्धि को मजबूती का प्रतीक बताया

नई दिल्ली(ए)। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी के 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की मजबूती और उस ठोस आधार को दिखाता है, जिसे पिछले 12 वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के जरिए तैयार किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा केंद्र का कलेक्टर ने किया निरीक्षण



रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज सुबह सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा केंद्र जे.आर. दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्मी को देखते हुए केंद्र में कूलर, उंडे पेयजल, ओआरएस, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा दल की व्यवस्था की गई है निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम नंदकुमार चौबे, रोजगार अधिकारी केदार पटेल तथा तहसीलदार राममूर्ति दीवान उपस्थित रहे।



वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर को कमतर आंकने की कोशिश की है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें फिलहाल 96 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। ट्रंप का दावा है कि लोग इसके 300 डॉलर तक पहुंचने की आशंका जता रहे थे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी तरफ, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही ठप पड़ी है, जिससे तनाव लगातार गहराता जा रहा है। ईरानी नेतृत्व को भरोसा है कि अमेरिकी को चुनौत से पहले युद्ध विरोधी जनभावनाओं के कारण ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा।

असली दुश्मन पहचानें: लेबनानी राष्ट्रपति ओन के बयान पर ईरान का पलटवार, कहा- अपने देश को बचाएं

ईरानी विदेश मंत्रालय ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ओन ने आरोप लगाया था कि ईरान अपने क्षेत्रीय हितों के लिए लेबनान का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के साधन के रूप में करता है। *लेबनान के राष्ट्रपति ने क्या आरोप लगाया?* विवाद तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति ओन ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अपनी कूटनीतिक बातचीत में लेबनान को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। *ईरान के विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया* इसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी टिप्पणी की। बघाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो लोग उनके (लेबनान के राष्ट्रपति) साथ रहते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और जो उनके खिलाफ होते हैं, उनके साथ हो जाते हैं।

संपादकीय

पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी अंदरूनी संकट से जूझ रही है। ममता बनर्जी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विधायकों की बैठक में कम उपस्थिति, निष्कासन और बगावत के दावों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कार्यकर्ताओं में बेचैनी और नेताओं की नाराजगी के बीच पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से टीएमसी

लगातार परेशानियों में घिरी हुई है। सत्ता से दूर होते ही पार्टी के भीतर का असंतोष सतह पर आ गया है। और अब जिस तरह की खींचतान चल रही है, उसे देखते हुए ऐसी अटकलें लग रही हैं कि क्या पार्टी टूट जाएगी। ममता बनर्जी की छवि जुझारू नेता की है, जिन्होंने हर सियासी लड़ाई खुद जमीन पर उतर कर लड़ी। 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार के खिलाफ उपजे असंतोष को आवाज देकर 2011 में

वह सीएम पद तक पहुंची थीं। 15 साल बाद जब वह विपक्ष में हैं, तो फिर से सड़क की राजनीति कर रही हैं। चुनाव बाद हिंसा के विरोध में मंगलवार को उन्होंने कोलकाता में धरना दिया। उन्होंने भाजपा पर चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वह लड़ते हुए दिखना चाहती हैं, ताकि पार्टी को हार की हताशा से निकाल सकें, लेकिन इस बार मुश्किल बड़ी दिख रही है। 1998 में अपनी स्थापना के बाद

से टीएमसी शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर एकजुटता को लेकर सवाल हैं। ममता ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 80 में से केवल 20 पहुंचे। फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दो विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। इन्हीं विधायकों ने फर्जी हस्ताक्षर मामले में शिकायत की है, जो अगर सही पाई जाती है तो मुश्किल और बढ़ेगी। इस

बीच निर्लंबित प्रवक्ता रिजु दत्ता का दावा है कि 50 विधायक टीएमसी से टूट कर पार्टी सिंबल पर दावा कर सकते हैं। इधर देखा जा रहा है कि चुनावी हार के बाद पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु में भी परिणाम के बाद एआईएडीएमके में बगावत की खबरें आईं। महाराष्ट्र में कुछ साल पहले शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी। और बंगाल में तो वैसे भी

सत्ताधारी दल का पूरी व्यवस्था पर कब्जा रहता है। इसमें विपक्ष के लिए शायद ही गुंजाइश बचती हो। लेफ्ट के शासन में टीएमसी इसी संकट से जूझ रही थी और जब टीएमसी आई, तो भाजपा ने इसी तरह की परेशानी उठाई। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा एक बड़ा मुद्दा है ही, जिसकी वजह से निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में डर और बेचैनी होती देखना होगा कि इसका क्या असर होता है।

दवाओं, ई-कॉमर्स, डायनामिक प्राइसिंग, चिकित्सा उपकरणों, सेवा क्षेत्र और मूल्यनियंत्रण नीति जैसे क्षेत्रों में कीमतें आखिर कैसे तय होती हैं? यह लेख मूल्यनिर्धारण की मौजूदा व्यवस्था, मुनाफे के गणित और उपभोक्ता हितों पर पड़ रहे उसके प्रभाव की विस्तृत पड़ताल करता है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश की विशाल जनसंख्या, बढ़ती क्रय क्षमता, डिजिटल विस्तार और उपभोक्तावादी संस्कृति ने भारतीय खुदरा बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अनुमान है कि वर्ष 2035 तक यह बाजार दोगुनी क्षमता हासिल कर लेगा।

बाजार में कीमतें कौन करता है तय? एमआरपी के पीछे छिपे फार्मूले और मुनाफे की सच्चाई

(विनोद के शाह)

दुनिया की सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें भारत के इसी विशाल उपभोक्ता बाजार पर टिकी हुई हैं। इसके साथ देश में ऑनलाइन व्यापार का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 19 फीसद की दर से बढ़ता ई-वाणिज्य क्षेत्र आज भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई-वाणिज्य बाजार बनने का दर्जा हासिल किया। पिछले वर्ष देश का ऑनलाइन खुदरा व्यापार लगभग 65 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें करीब तीस करोड़ सक्रिय उपभोक्ता रहे हैं। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह आंकड़ा 190 अरब डॉलर का होगा।देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग दस फीसद का योगदान देने वाला खुदरा व्यापार न केवल अर्थव्यवस्था की गति तय करता है, बल्कि महंगाई और मुद्रास्फीति के आंकड़ों को भी सीधे प्रभावित करता है। विडंबना यह है कि इतने विशाल और प्रभावशाली बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर सरकार का कोई प्रभावी नियंत्रण दिखाई नहीं देता। बाजार में अधिकांश वस्तुओं की कीमत निर्माता स्वयं तय करता है और उपभोक्ता के पास उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। वर्ष 2013 में बाजार आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू किया गया। सरकार ने वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना अनिवार्य तो कर दिया, लेकिन यह तय करने की कोई वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की कि किसी वस्तु की कीमत किस आधार पर तय होगी।

परिणामस्वरूप मूल्य निर्धारण का पूरा अधिकार निर्माता कंपनियों के हाथों में चला गया। निर्माता उत्पादन लागत, बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन खर्च, वितरण शृंखला, कमीशन और अंशित मुनाफे को जोड़कर अपनी सुविधा अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर देते हैं। 'लोगल मेट्रोलांजी अधिनियम' और 'पैकेज्ड क्मोडिटी नियम' केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलना अपराध माना जाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह मूल्य तय करने का वास्तविक आधार क्या होगा।

इसी सबसे बड़ी खामी ने उपभोक्ता संरक्षण की भारतीय अवधारणा को कमजोर किया है। स्थिति यह है कि ग्राहक को केवल पैकेट पर अंकित कीमत दिखाई जाती है, जबकि उस वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत उससे कई गुना कम हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण कानून ग्राहक को केवल मोलभाव का अधिकार देता है, लेकिन जब ग्राहक को वस्तु की वास्तविक लागत ही ज्ञात नहीं हो, तब मोलभाव का औचित्य मात्र औपचारिकता ही है।

देश की अधिकतम खुदरा मूल्य व्यवस्था उपभोक्ता हित के बजाय कंपनियों और मुनाफाखोर व्यापारिक तंत्र को संरक्षित करती प्रतीत होती है। अनेक उत्पादों में अधिकतम खुदरा मूल्य

उत्पादन लागत से कई गुना अधिक रखा जाता है। जहां प्रतिस्पर्धा कम होती है या विकल्प सीमित होते हैं, वहां निर्माता उपभोक्ताओं से मनमाना मूल्य वसूलते हैं। किसी क्रीम, फेसवॉश या कॉस्मेटिक उत्पाद की कीमत उसके वास्तविक गुणों से अधिक उसके विज्ञापन पर निर्भर करती है। करोड़ों रुपए के प्रचार अभियान उपभोक्ताओं की मानसिकता को प्रभावित करते हैं और उत्पाद का मूल्य कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ा दिया जाता है। दवा बाजार की स्थिति भी चिंताजनक है। सरकार ने कभी सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दिया था, लेकिन आज वही क्षेत्र मूल्य निर्धारण की सबसे बड़ी विसंगति का प्रतीक बन गया है।

यह एक अपवाद नहीं, बल्कि भारतीय दवा बाजार की वास्तविकता है। मरीज चिकित्सक के लिखे पर्चे के साथ पहली दुकान पर पहुंचता है, तो उसे वह जेनेरिक दवा अधिकतम खुदरा मूल्य या मामूली छूट के साथ दी जाती है। मगर वही मरीज जब अलग-अलग दुकानों पर कीमत की जानकारी लेता



है, तो उसी ब्रांड की वही जेनेरिक दवा दस गुना कम कीमत पर भी उपलब्ध हो जाती है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण सूची में केवल कुछ गंभीर बीमारियों की दवाओं को ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखा गया है। शेष दवाओं की कीमतें पूरी तरह कंपनियों और वितरकों की इच्छा पर निर्भर हैं। मरीजों से वसूली जाने वाली राशि में वास्तविक दवा लागत से अधिक कमीशन, ब्रांडिंग और व्यापारिक लाभ शामिल होते हैं। चिकित्सा उपकरणों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। आंखों में लगाए जाने वाले लेंस, हृदय रोग में प्रयुक्त स्टेंट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में भारी असमानता दिखाई देती है।

ऑनलाइन बाजार ने मूल्य निर्धारण की विसंगतियों को और अधिक जटिल बना दिया है। उपभोक्ता को आकर्षित करने के

लिए 'एक के साथ एक मुफ्त', 'अविश्वसनीय छूट', 'फ्रेडिट कार्ड ऑफर' और 'कैशबैक' जैसे प्रलोभनों का सहारा लिया जाता है। एक ही वस्तु अलग-अलग भुगतान माध्यमों पर अलग-अलग कीमतों में उपलब्ध कराई जाती है। यह व्यवस्था न केवल उपभोक्ता के साथ भेदभाव है, बल्कि उसे अतिरिक्त बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ने के लिए भी बाध्य करती है। विदेशी ब्रांडों को भारतीय बाजार में कई गुना अधिक कीमत पर बेचा जाता है। विडंबना यह है कि खुले बाजार में इन्हीं ब्रांडों के नाम पर कली उत्पादों की भरमार है। महामारी से लेकर युद्ध से उपजे संकट तक में बाजार में मुनाफाखोरी बढ़ती है। मूल्य नियंत्रण की प्रभावी नीति के अभाव में उपभोक्ता महंगाई का शिकार होता रहा है।

सेवा क्षेत्र में भी यही स्थिति दिखाई देती है। विमान कंपनियां मांग के अनुसार टिकटों की कीमतें बदलती रहती हैं। बीमा कंपनियां जोखिम और बाजार परिस्थिति के आधार पर प्रीमियम तय करती हैं। होटल, परिवहन और डिजिटल सेवाओं में भी 'डायनामिक प्राइसिंग' के नाम पर उपभोक्ता से अधिकतम

वसूली की जाती है। इससे साफ है कि देश में बढ़ती महंगाई के पीछे केवल उत्पादन लागत में वृद्धि जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का अनियंत्रित तथा मनमाना मूल्य निर्धारण भी एक बड़ा कारण है। यह समय की मांग है कि सरकार मूल्य निर्धारण में लागत आधारित पारदर्शी नीति

तैयार करे। किसी भी वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य उसके वास्तविक उत्पादन खर्च, कर, परिवहन और सीमित लाभांश के आधार पर तय होना चाहिए, न कि केवल बाजार की मांग और उपभोक्ता की मजबूरी के आधार पर। देश में आवश्यक वस्तुओं, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, शिक्षा सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए स्वतंत्र मूल्य तय करने के वास्ते मूल्य निर्धारण आयोग का गठन किया जा सकता है। उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार मिलना चाहिए कि जिस वस्तु के लिए वह भुगतान कर रहा है, उसकी वास्तविक लागत क्या है और उस पर कितना लाभ जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाजार का उद्देश्य केवल व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना भी होना चाहिए। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

इलाज का ‘मानक’ ही पुरुष शरीर बन गया, तब पीछे छूट गई महिलाओं की सेहत

(अमरपाल शर्मा)

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों महिलाएं आज भी ऐसी जिंदगी जी रही हैं, जिसमें दर्द है, उपेक्षा है, गलत इलाज है और एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो अब भी पुरुष शरीर को 'मानक' मान कर चलती है। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति होने के बावजूद महिलाओं के लिए समान और संवेदनशील इलाज अब भी एक चुनौती है। विश्व में महिलाओं की औसत आयु लगभग 73.8 वर्ष है, जो पुरुषों की औसत आयु करीब 68.4 वर्ष से अधिक है। फिर भी उनके जीवन का लगभग पच्चीस फीसद से अधिक समय खराब सेहत के साथ गुजरता है। यानी महिलाएं लंबे समय तक पुरानी बीमारियों और लगातार पीड़ा से त्रस्त रहती हैं। वे कई बार बिना इलाज या गलत निदान से भी जूझती हैं।

सवाल है कि आखिर महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें, तो इस स्थिति के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है।

शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रहीं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को 'भावनात्मक', 'हार्मोन संबंधी' या सामान्य कह कर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने बार-बार इस बात पर

जोर दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अनेक संरचनाएं महिलाओं को केंद्र में रख कर नहीं बनाई गईं। इसे केवल अस्पतालों की कमी कह कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जिसमें पुरुष शरीर को 'सामान्य' और महिला शरीर को 'विशेष परिस्थिति' मान लिया जाता है।

दुनिया भर में हृदय रोग महिलाओं की मौत की



सबसे बड़ी वजहों में शामिल है, लेकिन दिल के दौरों के जिन 'सामान्य' लक्षणों को चिकित्सा जगत लंबे समय से पहचानता रहा है, वे अधिकतर पुरुषों के अनुभवों पर आधारित रहे हैं। महिलाओं में दिल की बीमारी के संकेत कई बार अलग रूप में सामने आते हैं। अत्यधिक थकान, मितली, सांस फूलना, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे लक्षणों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता।

महिलाओं में हृदय रोग का पता अक्सर देर से चलता है

यही वजह है कि महिलाओं में हृदय रोग का पता अक्सर देर से चलता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद महिलाओं में मृत्यु का खराब पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। कई मामलों में उनकी शिकायतों को

सामान्य मान कर अस्पताल से वापस भेज दिया जाता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी तरह माहवारी, माइग्रेन, हार्मोन असंतुलन और रजोनिवृत्ति जैसी समस्याओं को अक्सर 'सामान्य' कह कर टाल दिया जाता है। लाखों महिलाएं वर्षों तक दर्द सहती रहती हैं। इस कारण कई बार उनकी गंभीर बीमारियां छिपी रह जाती हैं। अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में मातृत्व पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। गर्भावस्था, प्रसव और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में सुधार भी हुआ है। जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन समस्या यह है कि महिला स्वास्थ्य को अब भी 'मातृत्व' तक सीमित कर दिया जाता है। जबकि एक महिला की पहचान केवल मां के रूप में ही नहीं होती। किशोरावस्था, कामकाजी जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और रजोनिवृत्ति से जुड़ी उसकी जरूरतों पर अब भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

'द लासेट' में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार पिछले तीन दशकों में दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि हाल के वर्षों में इस सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग करीब ढाई लाख महिलाओं की मौत गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई। इससे स्पष्ट है कि आज भी अनेक देशों, विशेषकर निम्न और मध्य आय वाले देशों में मातृत्व महिलाओं के लिए जोखिम भरा है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मातृ मृत्यु के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2023 में देश में करीब 24,700

महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित कारणों से हुई। मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। घरेलू दबाव, आर्थिक निर्भरता, हिंसा, सामाजिक अपेक्षाएं और लगातार श्रम उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं अवसाद, चिंता और मानसिक थकान का इलाज नहीं करा पातीं। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच भी है। महिलाओं की तकलीफ को अक्सर कमजोरी, ज्यादा सोचने की आदत या घरेलू चिंता कह कर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांवों में स्थिति और जटिल है। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी, महिला चिकित्सकों की कमी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संकोच मिल कर महिलाओं के लिए इलाज को कठिन बना देते हैं। कई परिवारों में पुरुष सदस्यों की बीमारी को लेकर ही चिंता की जाती है, जबकि महिलाएं तब तक इलाज नहीं कराती, जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से बार-बार यह बात सामने आई है कि देश में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया और कुपोषण की शिकार हैं। ऐसे में हालात बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। विद्यालय स्तर पर किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति के बारे में जरूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य को शर्म के बजाय जब सामान्य स्वास्थ्य की तरह देखा जाएगा, तभी स्थितियां बदलेंगी। कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए संवेदनशील नीतियां बनानी होंगी। वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में अधिक महत्व देना होगा, क्योंकि अक्सर उनकी समस्याओं को 'उम्र का असर' कह कर टाल दिया जाता है। हमें यह समझना होगा कि महिला स्वास्थ्य केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है।

चीनकेलिएकरताथा जासूसी: अमेरिकी पत्रकार ने कोर्टमेंकबूला गुनाह

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक चौंकाने वाले मामला सामने आया है। चीन में लंबे समय से रह



रहे अमेरिकी पत्रकार थॉमस पाउकेन द्वितीय ने अदालत में स्वीकार किया है कि वह बिना कानूनी अनुमति के चीनी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, पाउकेन ने चीन के लिए जानकारी जुटाने और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करने का काम किया। दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी और उसे अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, पाउकेन कम से कम 2019 से चीनी एजेंटों के संपर्क में था। वह कैथी नाम की एक महिला के लिए रिपोर्ट तैयार करते थे, जिसे वह चीन की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मानते थे। आरोप है कि 2019 से 2025 के बीच उसे इन रिपोर्टों के बदले करीब एक लाख डॉलर और अमेरिका की कई प्रायोजित यात्राएं मिलीं। पाउकेन का दावा था कि उनकी रिपोर्टें सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंचती थीं। एफबीआई के अनुसार, पाउकेन ने ऐसे लोगों की तलाश की जो अमेरिकी प्रशासन में नौकरी हासिल कर सकते थे और बाद में संवेदनशील या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंचा सकें। फरवरी 2025 में वाशिंगटन में हुई एक बैठक के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को सिम कार्ड दिया और उसे हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार करने के बदले 10,000 डॉलर देने का प्रस्ताव रखा। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन रिपोर्टों का उद्देश्य अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करना था। अदालती दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया है कि जनवरी 2025 में अमेरिका लौटने पर पाउकेन ने अधिकारियों को बताया था कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जो ट्रंप प्रशासन में नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने माना था कि ट्रंप हैं 80 प्रतिशत यकीन है कि वह व्यक्ति नौकरी मिलने के बाद चीन को गोपनीय जानकारी दे सकते हैं।

वादे से पलटे ट्रंप?: अमेरिका को दुनियाभर के संघर्षों में उलझा रहे राष्ट्रपति

वाशिंगटन, एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में चुनाव जीतने से पहले तक लगातार अमेरिकी जनता से नए-नए वादे करते आ रहे थे। फिर चाहे अमेरिका को नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा हो या फिर अमेरिकी जनता को महंगाई से बचाने का। इन अधिकतर वादों में से कई पर या तो काम जारी है या स्थितिया ट्रंप के अनुकूल नहीं हैं। हालांकि, एक वादा जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक खुद ही पलटते दिखे हैं, वह वादा है अमेरिका को दुनियाभर में जारी संघर्षों से निकालने का। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सामने आता है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका संघर्षों से निकलने के बजाय कुछ और नए युद्ध में उलझता ही चला गया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले और इस दौरान दुनियाभर के युद्ध से अमेरिका को निकालने पर वया वादे किए थे? कैसे ट्रंप धीरे-धीरे इन वादों से लगातार पलटें हैं? फिलहाल अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को ट्रंप ने किस तरह बढ़ाया है? कैसे ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में भी कुछ ऐसे ही वादे तोड़े थे? आइये जानते हैं... डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश करने के साथ चुनाव प्रचार के दौरान खुद को ‘शांति के उम्मीदवार’ के रूप में पेश किया था और अमेरिका को विदेशी युद्धों से बाहर निकालने को लेकर कई बड़े और स्पष्ट वादे किए थे। अनंत संघर्षों का अंत : ट्रंप ने एक दशक तक लगातार यह वादा किया कि वह पश्चिम एशिया के लंबे संघर्षों और खत्म न होने वाले संघर्षों को रोकेंगे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के शासन में जॉर्ज बुश की तरफ से शुरू किए गए इराक युद्ध को एक बड़ी गलती करार दिया था। ट्रंप का कहना था कि इसने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे देशों के मामलों में दखल और अराजकता की नीतियों को खत्म करने की बात कही थी।

दूषित भोजन बना वैश्विक संकट: हर साल 86 करोड़ से अधिक लोग बीमार

जिनेवा, एजेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की नई रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार दूषित और असुरक्षित भोजन के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 86.6 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, जबकि करीब 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस संकट का सबसे अधिक असर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर तत्काल और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुनिया की आबादी का केवल लगभग 9 प्रतिशत हैं, लेकिन भोजनजनित बीमारियों के करीब एक-

तिहाई मामलों का बोझ इन्हीं पर पड़ता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण वे संक्रमण व विषैले तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दूषित भोजन से होने वाले डायरिया जैसे संक्रमण बच्चों में तेजी से फैलते हैं और कई मामलों में जानलेवा साबित हो सकते हैं। वहीं भोजन में मौजूद सीसा और मिथाइलमरकरी जैसे जहरीले तत्व बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उनकी दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में भोजनजनित बीमारियों के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। जैविक और रासायनिक खतरें। जैविक खतरों में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी शामिल

गाजा में फिर भीषण हवाई हमले, महिलाओं-बच्चों समेत 10 की मौत; सीजफायर के बीच भी जारी हिंसा

गाजापट्टी, एजेंसी। भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहाली ने कठिन समय में भारतीय जनता द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जब ईरान अपने दो प्रमुख नेताओं को खोने के गहरे दुख से गुजर रहा था, तब भारत के लोगों ने उनके साथ एकजुटता दिखाई और हर स्तर पर सहानुभूति व्यक्त की।

डॉ. फतहाली ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत के नागरिक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और ईरानी जनता के दुख में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि यह समर्थन केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की मानवीय संवेदनाओं और मित्रता का प्रतीक था।

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सीजफायर लागू होने के बाद भी अब तक 936 लोगों की मौत हो चुकी है।

मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा विश्वसनीय माना जाता



है, हालांकि यह नागरिकों और लड़कों का अलग-अलग आंकड़ा जारी नहीं करता। इस्राइल का कहना है कि हमले उन घटनाओं के जवाब में किए जाते हैं जिनमें समझौते का उल्लंघन या सुरक्षा खतरा शामिल होता है। इस्राइल की सेना ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में हुए हमलों में हम्लास के चार लड़कों को

मार गिराया गया है। सेना के अनुसार ये लोग हम्लास नेतृत्व की सुरक्षा और



खुफिया जानकारी से जुड़े थे। सेना ने यह भी कहा कि हमलों से पहले नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सटीक हथियारों और निगरानी का उपयोग किया गया। हालांकि शाम के हमले को लेकर सेना ने तत्काल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। गाजा पट्टी में इस्राइली हवाई हमलों ने एक बार फिर

10 न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम, ईरान के परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रही यूएन एजेंसी

वियना (ऑस्ट्रिया), एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों के बीच प्रसारित एक गोपनीय रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि पिछले जून में हुए युद्ध से प्रभावित ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने में उसे अब तक सफलता नहीं मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत सुरक्षा निगरानी संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में एजेंसी फिलहाल सक्षम नहीं है। जोर देकर कहा कि ईरान के लिए अपनी संधि संबंधी जिम्मेदारियों को तत्काल और पूरी तरह लागू करना अनिवार्य और अत्यावश्यक है। एजेंसी ने केवल ईरान के बुशेर क्षेत्र का दौरा किया फरवरी में जारी पिछली रिपोर्ट के बाद

से निरीक्षकों ने ईरान में केवल बुशेर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ही दौरा किया है। यह निरीक्षण 1 से 3 जून के बीच



किया गया था। बुशेर में संचालित रिएक्टर रूस से प्राप्त 4.5 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करता है, जो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक निम्न स्तर का संवर्धन माना

जाता है। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को ईरानी ड्रोन हमलों में कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी जांच कई अन्य घायल हुए। घटना के बाद हवाई अड्डे का संचालन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच जारी जवाबी कार्रवाइयों की शृंखला का हिस्सा माना जा रहा है,

क्यूबा के राष्ट्रपति पर अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध, ट्रंप बोले- इस मुद्दे को हम संभालेंगे

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल, उनकी पत्नी और कई बड़े अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने यह कदम क्यूबा की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया है। इन प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और तलखी आ गई है। क्यूबा ने अमेरिका के इस फैसले को अपनी संप्रभुता पर हमला और खुली दखलअंदाजी बताया है।

अमेरिका ने जिन लोगों पर कार्रवाई की है, उनमें पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के बेटे एलेजांद्रो कास्त्रो एरियन और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने इन सभी की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों और बैंक खातों को फ्रीज करने का फैसला किया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इन नेताओं की अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में बहुत कम हिस्सेदारी है। इसके बावजूद इस कदम को ट्रंप प्रशासन की कड़ी राजनीतिक चेतावनी माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार क्यूबा की सरकार पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हटाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी भी लागू की थी। इससे क्यूबा में ईंधन संकट, बिजली कटौती और खाद्य संकट

और गहरा गया। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा पहले से ही लगभग टूट चुका है और



अमेरिका इस मुद्दे को भी संभालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा के पास सुंदर जमीन और पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन वहां की सरकार देश को सही तरीके से नहीं चला रही।

क्यूबा ने अमेरिका के आरोपों पर क्या जवाब दिया?

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने अमेरिका पर नए तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन क्यूबा को झुकाने और वहां के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार ऐसा माहौल बनाने की

कोशिश कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच टकराव बढ़े। क्यूबा सरकार ने साफ कहा कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकेगी नहीं।

किन संस्थाओं और लोगों को निशाना बनाया गया?

अमेरिका ने सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, बल्कि क्यूबा की कई सरकारी और सामाजिक संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें क्यूबा का रक्षा मंत्रालय, ‘इंस्टीट्यूट फॉर द फ्रेंडशिप विद पीपल्स’, पर्यटन से जुड़ी संस्था एमिस्टुर क्यूबा और ‘कमेटीज फॉर द डिफेंस ऑफ द रिवोल्यूशन’ शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति डियाज-कैनेल की पत्नी लिस कुएस्ता पेराजा और उनके सौतेले बेटे मिगुएल एनियो कुएस्ता पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। राष्ट्राध्यक्षों और उनके परिवारों पर प्रतिबंध लगा चुका है।

सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर, जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगबे और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ट्रंप प्रशासन क्यूबा की मौजूदा सरकार को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इस दबाव से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं।

हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। स्थानीय अस्पतालों के अनुसार गुरुवार को हुए अलग-अलग हमलों में कम से कम 10 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमले ऐसे समय में हुए हैं जब क्षेत्र में पहले से ही जारी संघर्ष और सीजफायर के बावजूद हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गाजा सिटी में शिफा अस्पताल के अनुसार रातभर में चार अलग-अलग हमलों में नौ लोगों की मौत हुई। अस्पताल ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, रेड क्रॉस द्वारा संचालित सराया फील्ड अस्पताल ने बताया कि गुरुवार शाम हुए एक और हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक हमले में रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिल पर बड़ा धमाका हुआ, जिससे दीवारें टूट गईं।

जिसने पहले से नाजुक संघर्षविराम पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के पास वर्तमान में 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्तर हथियार-ग्रेड 90 प्रतिशत संवर्धन से तकनीकी रूप से बहुत दूर नहीं है। महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियारों में बदलने का निर्णय लेता है तो यह भंडार सैद्धांतिक रूप से लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि ईरान के पास फिलहाल परमाणु हथियार मौजूद हैं। एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इतने उच्च स्तर के संवर्धित परमाणु पदार्थ का सामान्य रूप से हर महीने सत्यापन किया जाना चाहिए।

रूस-अमेरिकाफिर आमने-सामने

ट्रंप बोले- भारत ने वर्षों तक हमारा फायदा उठाया, पुतिन ने बताया भरोसेमंद साझेदार

वॉशिंगटन/मॉस्को, एजेंसी।

भारत को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने और अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। दोनों महाशक्तियों के बयानों ने साफ कर दिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को अपने-अपने नजरिए से देख रही हैं।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रूस भारत के साथ अपने पुराने और भरोसेमंद रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से विकास कर रहा है। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से भारत पर रूस से दूरी बनाने के लिए डाला गया दबाव बेअसर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापार आने वाले वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार की मेहनत का परिणाम है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होने से रूस को कोई परेशानी नहीं है। पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताते हुए कहा कि रूस भारत के साथ

टैरिफ और व्यापार समझौते पर क्यों बढ़ा तनाव?

अमेरिका ने हाल ही में भारत समेत 54 देशों पर अतिरिक्त 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका का आरोप है कि इन देशों से आने वाले कुछ सामान जबरन श्रम के जरिए तैयार किए जाते हैं। ट्रंप ने हार्लैं-डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में पहले अमेरिकी बाइक कंपनियों पर 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाता था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कंपनी को भारत में अपना प्लांट लगाना पड़ा। वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और टैरिफ कम करने पर चर्चा कर रहे हैं।

भारत की बढ़ती ताकत पर दुनिया की नजर क्यों?

रूस और अमेरिका के ताजा बयानों से साफ है कि भारत अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। एक तरफ रूस भारत को भरोसेमंद साझेदार मान रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नए तरीके से देख रहा है।

हर क्षेत्र में संबंध बढ़ता रहेगा। पुतिन के बयान को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है जब पश्चिमी देश लगातार भारत से रूसी तेल खरीद कम करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर सख्त बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने वर्षों तक अमेरिका की नीतियों का फायदा उठाया।

सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने दी जानकारी

किम जोंग ने दिखाई नई परमाणु फैक्टरी: हथियारों का जखीरा बढ़ाने का किया एलान; यूएस-दक्षिण कोरिया की बढ़ी चिंता

प्रतिरोधक क्षमता को मात्रा और गुणवत्ता दोनों में मजबूती देना



जरूरी हो गया है। उन्होंने अन्य वैश्विक संकटों और सुरक्षा चुनौतियों का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि बीते पांच साल में देश की हथियार-स्तर परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता दोगुने से अधिक बढ़ चुकी है। परमाणु गतिविधियों को तेज करने पर आईएईए का खुलासा उत्तर कोरिया के सितंबर 2024 में सामने आए एक अन्य गुप्त यूरेनियम संवर्धन संयंत्र के बाद सामने आया है। अमेरिकी विद्वानों को 2010 में 'योंगव्योन परमाणु परिसर दिखाने के बाद दूसरी बार

उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक तौर से ऐसा संयंत्र दिखाया है। यहां 2017 के बाद भले ही कोई परमाणु परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु-सक्षम मिसाइलों का तेजी से विकास किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया के पास अब 100 से अधिक विनाशकारी परमाणु वारहेड हो सकते हैं और वह हर साल 6 से 18 नए हथियार बनाने में सक्षम हो सकता है।

दुनिया की बड़ी फिर्कः- दक्षिण कोरियाई सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस स्थल को यूरेनियम संवर्धन केंद्र बताते हुए कहा कि वह उत्तर कोरिया की परमाणु गतिविधियों पर अमेरिका के साथ मिलकर नजर रख रहा है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया चार यूरेनियम संवर्धन केंद्र संचालित कर रहा है। 2019 में अमेरिका के साथ वार्ता नाकाम होने के बाद किम ने परमाणु शास्त्रांगार के विस्तार पर और जोर दिया है।

हमको ताकत के साथ दुश्मन की साजिश नाकाम करनी होगी, यूएस से तनाव के बीच सामने आया खामेनेई का संदेश

तेहरान, एजेंसी। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामेनेई के नाम से एक संदेश इमाम खुमेनी के 37वें पुण्यतिथि समारोह के दौरान उनके मकबरे पर पढ़ा गया। यह जानकारी तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार है। तसनीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, संदेश के माध्यम से सर्वोच्च नेता ने कहा, ‘सभी को दृढ़ता, दूरदर्शिता, एकता और आपसी विश्वास को बनाए रखते हुए और शत्रु की बातों का समर्थन न करते हुए शत्रु की साजिश को विफल करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘खुदाई के चौदहवें दिन के शहीद नेता ने इसे इमाम खुमेनी (आरए) के साथ राष्ट्र की प्रतिज्ञा के लिए एक वार्षिक अवसर में बदल दिया है।’ संदेश में ईरान के क्रांतिकारी नेतृत्व के साथ वैचारिक निरंतरता पर और जोर दिया गया। उन्होंने कहा, ‘ ईरानी राष्ट्र, अपने नए मिशन के साथ, प्रतिरोध के साथ—साथ स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए गौरव का स्रोत बन गया है।’ इस संदेश में इस्राइल के साथ क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों का भी साफ जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था, ‘अस्थिर जायेंनी शासन और इस्राइल का घातक टट्टुमर अपने भयावह जीवनकाल के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। ईश्वर की कृपा से और दस वर्ष पूर्व शहीद नेता के दृढ़ और दूरदर्शी शब्दों के अनुसार, ईश्वर की इच्छा से वह उस तिथि के बाद 25 वर्ष नहीं देह पाएंगे।

मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच बड़ी खुशखबरी भारत को मिला गैस का भंडार

नई दिल्ली, एंसेंसि

सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान ऑफशोर बेसिन में एक नई नेचुरल गैस की खोज की है। यह ऐसे समय में हुआ है जब कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और जियोपॉलिटिकल तनाव ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस खोज लिए ऑयल इंडिया को बधाई दी है। कंपनी ने बताया कि उसे अपने तीसरे एक्सप्लोररी वेल (खोज के लिए खोदें गए कुएं), विजयपुरम-3 में गैस मिली है। इसे ओपन एंक्लेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत एन-एन-एएसएचपी 2018/1-ब्लॉक में खोदा गया था।

कुएं की यह है लोकेशन

यह कुआँ अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर, 355 मीटर गहरे पानी में खोदा गया था। इस खोज के साथ ऑयल इंडिया ने अब तक ब्लॉक में खोदे गए तीन एक्सप्लोरेटरी वेल में से दो में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी का पता लगा लिया है। कंपनी ने कहा कि इओसीन फॉर्मेशन में 1,900 मीटर से अधिक की गहराई पर शुक्रांती प्रोडक्शन टेस्टिंग से नेचुरल गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ऑयल ने अपनी फॉर्मेशन में कहा, इओसीन फॉर्मेशन में 1900 मीटर से अधिक की गहराई पर कुआँ की शुक्रांती प्रोडक्शन टेस्टिंग से लगातार फ्लेयरिंग के जरिए नेचुरल गैस की मौजूदगी का पता चला है।



दूसरी बड़ी कामयाबी

यह नई खोज सितंबर 2025 में विजयपुरम-2 एक्सप्लोरेटरी वेल में नेचुरल गैस मिलने की खबर के बाद हुई है। ऑयल इंडिया ने बताया कि उसने पहले की खोज के लिए पहले ही एक अप्रेंटल प्रोग्राम शुरू कर दिया है। कंपनी ने ब्लॉक में उपलब्ध 2डी सिस्मिक डेटा की प्रीप्रोसेसिंग और अतिरिक्त 600 वर्ग किलोमीटर के 3डी सिस्मिक डेटा का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। सिस्मिक डेटा की प्रीप्रोसेसिंग और इंटरप्रीटेशन का काम अभी चल रहा है। इसके बाद अप्रेंटल वेल खोदने की योजना है। ऑयल इंडिया के मुताबिक, चूँकि अंडमान शैलो ऑफ़शोर ब्लॉक में चल रहे एक्सप्लोरेशन कैम्पेन के दौरान हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी का यह दूसरा मामला है। इसलिए हम अपने महत्वपूर्ण स्ट्रेटिजीकल को इसकी जानकारी देना चाहते हैं।

पेट्रोलियम मंत्री ने जाहिर की खुशी

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों एक्स पर लिखा, अंडमान सागर में ऊर्जा के अवसरो का भंडार! यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किमी दूर, 355 मीटर की गहराई पर खोदे गए श्री विजयपुरम-3 नाम के एक्सप्लोरेटरी वेल में प्राकृतिक गैस मिली है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस की यह मौजूदगी हमें ग्लोबल डीप-वॉटर एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अपने एक्सप्लोरेशन के दायरे को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अमृत काल की हमारी यात्रा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी!



ईंधन की महंगाई दर नियंत्रित रही। मुख्य महंगाई मार्च-अप्रैल के दौरान 3.7 प्रतिशत पर स्थिर रही। कीमती धातुओं को छोड़कर मुख्य महंगाई इसी अवधि में और कम होकर 2.1-2.2 प्रतिशत रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें (भारत पर भार) अप्रैल-

लागत बढ़ने के दूसरे चरण के प्रभाव आगे चलकर महंगाई पर दबाव डाल सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय महतोत्र ने जून माईकन की नीति घोषणा करते हुए कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जिस की कीमतों में झटके, मासूम की लेकर अर्निश्वितता और अल नीनी जैसी परिस्थितियों के कारण महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। फरवरी में 3.2 प्रतिशत से थोड़ा बढ़ने के बावजूद मार्च और अप्रैल 2026 में कुल खुदरा महंगाई लक्ष्य से नीचे (ऋणः) प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत) रही। खाद्य महंगाई में कुछ बढ़ोतरी हुई, जनक मार्च और अप्रैल में पेट्रोल-डीजल की कीमतों स्थिर रहने से

मई, 2026 के दौरान औसतन लागत 110 डॉलर प्रति बैरल रही हैं। ऐसे संकेत हैं कि 2026-27 में औसत कीमतों पिछली नीति में अनुमानित स्तर से काफी अधिक रहेगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों और कई कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के कारण अप्रैल, 2026 में कुछ महंगाई (डब्ल्यूपीआई) में तेज उछाल देखा गया। तिमाही आधार पर खुदरा महंगाई का अनुमान पहली तिमाही में 4.2 प्रतिशत, दूसरी में 5.1 प्रतिशत, तीसरी में 5.9 प्रतिशत और चौथी में 5.4 प्रतिशत लगाया गया है। 2026-27 के लिए कुल महंगाई 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 116, निफ्टी 49 अंक गिरा

मुम्बई।
भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबार दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजार से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इसकी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 116.67 अंक नीचे आकर 74243.34 के स्तर पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एम्प्लॉय अंकों की गिरावट के साथ ही 23 पर बंद हुआ। आज कारोबार के पर सेंसेक्स करीब 355 74,717.57 के स्तर पर पहुंच गया बाद अचानक ही इसमें गिरावट के कारोबार के दौरान सेंसेक्स वै अच्ची खरीदारी रही। वे हैं अडा फाइनेंस, एक्सिस बैंक और एम्प्लॉय ओर टाटा स्टील, टीसीएस और ए



नफ्टी 49.85	शेयरों में गिरावट रही जबकि नफ्टी के साथ ही मिड	भी बाजार गिरा
36.7 के स्तर	और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही।	बाजार तेजी
अ एक समय	इस कारण नफ्टी मिडिंक्पे 100 इंडेक्स 0.37	197.90 अंकों
क उछलकर	नफ्टी नीचे आ गयाजबकि नफ्टी स्मॉलकैप	के स्तर पर का
था पर इसके	100 इंडेक्स 0.13 फीसदी गिरा। आज कारोबार	एक्सचेंज का
लगी। आज	के दौरान अधिकतर इंडेक्स लाभ के साथ बंद हुए।	51.41 अंकों
नफ्टी शेयरों में	आज सबसे ज्यादा खरीदारी नफ्टी मीडिया में रही	महत्वपूर्ण स्तर
पोर्ट, बजाज	और यह करीब 3.50 फीसदी तक ऊपर आया।	शुरुआती कारो
मा। वहीं दूसरी	इसके अलावा नफ्टी ऑटो, एंफेएससीजी, फार्मा,	भी बाजार संस
नीएल टूकरी	पीएसयू बैंक, निजी बैंक, रियल्टी, हेल्थकेयर और	के शेयरों में नि

कजुमर इयूरोबल्स इंडेक्स के शेयर भी लाने के साथ बंद हुए। दूसरी ओर निफ्टी मेटल इंडेक्स काफ़ी 1.50 फीसदी और निफ्टी आईटी काफ़ी 4 फीसदी गया। बाजार जानकारों के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर संशय के बची ही बिनाई निवेशकों के बाजार से दूरी बनने के अलावा आब्रावीआई के आर्थिक विकास दर के कम होने और महंगाई बढ़ने की आशंका से रही। वहीं इससे पहले आज सुबह के साथ खुला। सुबह संसेकम की बढत के साथ 74,557.91 बाजार कब रही। वहीं नेशनल स्टॉक निफ्टी भी पीछे नहीं है और यह तेजी के साथ 23,467.95 के पर कामकाज कर रहा था। बाजार में आई-कैप शेयरों में तेजी से आगे आ रही और इफॉर्मरूक सेक्टर शकों ने रुचि दिखायी।

भी बाजार गिरा है। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला। सुबह संसेक्स 197.90 अंक की बढ़त के साथ 74,557.91 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पीछे नहीं है और यह 51.41 अंक की तेजी के साथ 23,467.95 के महत्वपूर्ण स्तर पर कामकाज कर रहा था। शुरुआती कारोबार में लाइन-कैप शेयरों में तेजी से भी बाजार सभला। आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों में निवेशकों ने रुचि दिखायी।



मिलेगा और करीब 14 हजार नौकरियों को सम्पन्न मिलेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस योजना से अमेरिकी उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में करीब 50 अरब डॉलर तक की बचत संभव होगी।
उन्होंने घोषणा की कि कई कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चालू रखने के लिए सरकार आपातकालीन अधिकारों का उपयोग करेगी। टूट के मुताबिक वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, नॉर्थ कैरोलाइना, इंडियाना, टेनेसी,

एरिजोना, अर्कांसस, ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा और विस्कांसिन सहित कई राज्यों के 13 कोयला बिजलीघरों को फैसले से राहत मिलेगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन बिजलीघरों के आधुनिकीकरण से उनकी संचालन क्षमता कई दशकों तक बनी रहेगी और देश के बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ट्रंप ने एक बड़े निर्यात कार्यक्रम की भी घोषणा करते हुए कहा कि वेस्ट गेटवे प्रोजेक्ट का निर्माण इस वर्ष गर्मियों में कार्यकाल में कोई नया कोयला पट्टा जारी नहीं हुआ था, जबकि वर्तमान प्रशासन ने 76 परमिट और लीज का मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी कोयले को आधुनिक महद्योगिक विकास और बिजली उत्पादन का अहम आधार बताया। ट्रंप ने कहा कि विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और घरेलू उद्योगों के विस्तार के लिए विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक है। कोयला इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

चांदी के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य

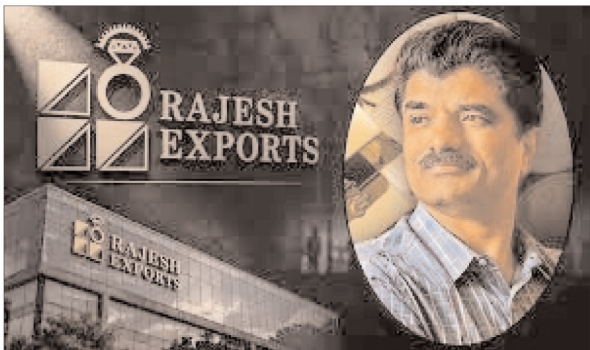


नियामकीय और तकनीकी ढांचे का अध्ययन शुरू कर दिया है। बीआईएस के अनुसार, व्यवस्था को पूरी तरह तैयार करने और संभावित कमियों

नई दिल्ली। देश में चांदी के गहनों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की तैयारी शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को शुद्धता की गारंटी देने और बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने इसके लिए को दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है, जबकि चांदी पर यह व्यवस्था लंबे समय से स्वीच्छक रूप में लागू है। प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद चांदी के गहनों की शुद्धता की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी और ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

को दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है, जबकि चांदी पर यह व्यवस्था लंबे समय से स्वैच्छिक रूप में लागू है। प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद चांदी के गहनों की शुद्धता की प्रमाणितता सुनिश्चित होगी और ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में भारी गिरावट



मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसकी शेयर खरीद रखे वही लगभग 600 करोड़ रुप का कर्ज के केनरा बैंक का है। हालिया घटनाक्रम के बाद शेयर में बिकवाली और तेज हो गई। स्टॉक लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। भारतीय प्रभुत्वित एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कंपनी और उसके प्रबंधन पर बीमा निगमों में कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू करते हुए कई प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। निगम की कार्रवाई को से निवेशकों का भ्रामक प्रभावित हुआ है। जिसका अरसर सीधे कंपनी है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसकी शेयर खरीद रखे हैं वही लगभग 600 करोड़ रुपए का कर्ज केनरा बैंक का है। हालिया घटनाक्रम के बाद शेयर में हलकवाली और तेज हो गई। स्टॉक लोअर सर्किट पर पहुंच गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कंपनी और उसके प्रबंधन पर वित्तीय खुलासे में कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू करते हुए कई प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। नियामक की कार्रवाई से निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है जिसका असर सीधे कंपनी के

बाजार पूंजीकरण और शेयर मूल्य पर दिखाई दे रहा है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के लिए पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनुशास्रीय स्तर पर कारोबार करने वाली कंपनी का यह घण्टा घोटाला सभी को चौंका रहा है। सेबी की जांच पूरी होने और तथ्यों के स्पष्ट होने तक निवेशकों में अमंजबग की स्थिति बन गई है। फिलहाल बाजार की नजर कंपनी के आगे की कार्रवाई और कंपनियों की स्पष्टीकरण के इंतजार पर टिकी हुई है। शेयर बाजार के घण्टे-घोटाले अब एक-एक करके सामने आ रहे हैं। राजेश एक्सपोर्ट के सामने सेबी जैसी संस्था भी बौनी साबित हो रही है। बार-बार जानकारी मांगने के बाद भी यदि उसके द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। तो समझ सकते हैं, यह कंपनी और इसके संचालक कितने पावरफुल हैं। उसके सिर पर किसका हाथ हो सकता है? इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है।

दो जनवरी, 2026 को समाप्त सप्ताह में 686.801 अरब डॉलर था

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 682 अरब डॉलर पर 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त: आरबीआई



उदारीकरण और अन्य कदम शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मई 2026 तक 682.3 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर था, जो लगभग 11 महीने के आयात और विदेशी

ऋण (89.1 प्रतिशत) जैसे भंडार पर्याप्तता के मानकों के हिसाब से पर्याप्त है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न नीतिगत पहलू भुगतान संतुलन को मजबूत करने में मदद करेंगे।



गवर्नर ने कहा कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे पास निर्यातकीय तथा बाजार-आधारित कई साधन हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

इस संदर्भ में हम सतर्क हैं और व्यवस्थित बाजार रीतिथि बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक होगा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मई को समाप्त सप्ताह में 7.51 अरब डॉलर घटकर 681.38 अरब डॉलर रहा। इस वर्ष 27

फरवरी को समाप्त सप्ताह में यह भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, लेकिन पश्चिम एशिया संघा शुरू होने के बाद कई सप्ताह तक इसमें गिरावट आई। इसका कारण रुपये पर दबाव बढ़ा और भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने और मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रसारण के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि 2025-26 में वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत ने ऊंचे शुल्क और व्यापार से जुड़ी अतिरिक्तताओं का सफलतापूर्वक सामना किया।

